भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2893
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्रगति

2893. डॉ. भोला सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के सृजन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) फसलोपरान्त हानि को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने पर उक्त पहलों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) अब तक कितने मेगा फूड पार्क संचालित किए जा चुके हैं और वे किन-किन क्षेत्रों में स्थित हैं; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केन्द्र प्रायोजित अम्ब्रेल्ला योजना प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है। मंत्रालय पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और संबंधित अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाओं की शुरुआत से अब तक 1187 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 666 परियोजनाएं चालू हैं, जिनसे 32,80,369 किसान लाभान्वित हुए हैं और 188.83 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष प्रसंस्करण क्षमता और 48.76 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष परिरक्षण क्षमता का सृजन हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्राथमिक सर्वेक्षणों के आधार पर अध्ययन करके देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर कटाई के बाद होने वाले नुकसान का अनुमान लगाता है । नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एनएबीसीओएनएस) द्वारा 2022 में किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार, कटाई और उपभोग के बीच फलों और सब्जियों में लगभग 5-13% और तिलहन और मसालों सहित अन्य फसलों में 3-7% कटाई के बाद होने वाले नुकसान का अनुमान है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इन हानियों को न्यूनतम करने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने के साथ-साथ प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमताओं के सृजन और विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

फसलें/वस्तुएं	**नुकसान (%)**	
	आईसीएआर-सीआईफेट अध्ययन (2015) के अनुसार*	**नैबकॉन्स अध्ययन (2022) के अनुसार****
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74

तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गीपालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

स्रोत: *भारत में प्रमुख फसलों और वस्तुओं की मात्रात्मक कटाई और कटाई के बाद के नुकसान के आकलन पर रिपोर्ट, 2015। ** नबकोंस अध्ययन 2022

(ग): मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत 25 विभिन्न राज्यों में 41 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, इनमें से 24 मेगा फूड पार्क परिचालित हैं। 24 परिचालित फूड पार्कों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**एसपीवी/आईए नाम**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जिले का नाम**
1	श्रीनि फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
2	गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	पश्चिमी गोदावरी
3	नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क लिमिटेड	असम	नलबाड़ी
4	इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ	रायपुर
5	गुजरात एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात	सूरत
6	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी)	हरियाणा	सोनीपत
7	क्रेमिका फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश	ऊना
8	इंटीग्रेटेड फूड पार्क लिमिटेड	कर्नाटक	तुमकुर
9	केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा)	केरल	पलक्कड़
10	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (केएसआईडीसी)	केरल	अलपुझा
11	इंडस मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	खरगोन
12	अवंती मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	देवास
१३	सतारा मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	सतारा
14	पैठन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
15	ज़ोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	मिजोरम	कोलासिब

16	एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लिमिटेड	ओडिशा	रायगढ़
17	इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क लिमिटेड	पंजाब	फाजिल्का
18	सुखजीत मेगा फूड पार्क एंड इंफ्रा लिमिटेड	पंजाब	कपूरथला
19	ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	अजमेर
20	स्मार्ट एग्रो फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	तेलंगाना	निजामाबाद
21	सिकरिया मेगा फूड पार्क (पी) लिमिटेड	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा
22	पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	उत्तराखंड	हरिद्वार
23	हिमालयन फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
24	जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद

(घ): पीएमकेएसवाई मांग आधारित प्रकृति की है और पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित नहीं करता है। पूर्वोत्तर राज्यों और दुर्गम क्षेत्रों [उत्तराखंड राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, राज्य अधिसूचित आईटीडीपी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना) क्षेत्र और द्वीप समूह (केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप] में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, योजना के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित उपाय शामिल किए गए हैं:

(i) सामान्य क्षेत्रों में 35% की तुलना में 50% की दर से अनुदान सहायता/सब्सिडी की उच्च दर;

(ii) निवल संपत्ति की आवश्यकता - सामान्य क्षेत्रों के लिए मांगे गए अनुदान-सहायता/सब्सिडी के 1.5 गुना के मुकाबले मांगे गए अनुदान-सहायता/सब्सिडी से कम नहीं

(iii) कम इक्विटी योगदान - सामान्य क्षेत्रों के लिए 20% के मुकाबले 10% आवश्यक;

(iv) कम ऋण आवश्यकता – सामान्य क्षेत्रों के लिए 20% की तुलना में 10% आवश्यक;

(v) परियोजना अनुमोदन के लिए निम्न पात्रता सीमा – अन्य के लिए 60 अंकों के मुकाबले 45 अंक; तथा

(vi) दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं के पूरा होने और चालू होने की अवधि 30 महीने है, जबकि सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 24 महीने है।

*****